

ग्रामीण विकास योजनाओं से नक्सलवाद से निपटेंगे जयराम

नई दिल्ली (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित पांच जिलों का दौरा करके लौटे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ग्रामीण विकास परियोजना के सहारे नक्सल समस्या की धार कुंद करने की फिराक में हैं। इसलिए जयराम नक्सलवाद की समस्या को केंद्र में रखकर योजनाओं में कुछ व्यावहारिक बदलाव के पक्ष में हैं।

जयराम के अनुसार इन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गति काफी दयनीय है। नारायणपुर और विजयपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास परियोजना का काम न के बराबर हुआ है। इन क्षेत्रों में तीन दिन तक बिजली नहीं आती। उनके मुताबिक ढाई साल पहले भी वह बस्तर गए थे। यह उनका बस्तर का तीसरा दौरा था, लेकिन आज भी वहां की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए वह इन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास

छग से लौटने पर किया अनुभव को साझा

कार्यक्रमों को सरकार और प्रशासन का 'इंटी प्वाइंट' बनाना चाहते हैं।

वह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गंगोरल बांध तीस साल पहले बना था, लेकिन अभी तक उसके विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य पूरा नहीं हो सका।

मलकागिरी में भी लोग दो बार विस्थापित हुए और वहां भी यही स्थिति है। जयराम का यह उदाहरण देने का आशय सरकारी तंत्र के लचर तरीके से काम करने का नमूना पेश करना भर था। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में डाक व्यवस्था का कारण न होना और स्वास्थ्य समस्या जैसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। स्थिति यह है कि सरकार कार्यक्रम लागू तो कर नहीं पा रही है ऊपर से आंकड़े दिखा रही है।

पर्यावरण मंत्रालय में शिखंडी बन कर रह गया था: रमेश

नई दिल्ली (प्रेटर)। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा, 'मैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में शिखंडी बन कर रह गया था।' महाभारत में शिखंडी को अर्जुन ने ढाल बना कर इस्तेमाल किया था। जयराम संवाददाताओं से जमीन अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, जिसका मसौदा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के वरिष्ठ सदस्यों और योजना आयोग के सदस्यों ने तैयार किया है। उन्होंने कहा, 'लेकिन मेधा पाटकर इस मसौदे की तैयारी में शामिल नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इस मसौदे से काफी खुश होंगी।'

नक्सल प्रभावित इन जिलों में से प्रत्येक को दो साल में 55 करोड़ रुपए दिए गए। जयराम को लगता है कि यदि कुशलता पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को इन क्षेत्रों में लागू किया जाए तो अगले 10-15 सालों में तस्वीर बदल सकती है। वह शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा के कंधमाल भी जाएंगे और नक्सल प्रभावित नौ जिलों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद झारखंड का भी दौरा होगा। जयराम का मानना है कि ये जिले जंगल, खनिज से पूर्ण और आदिवासियों के हैं। ज्यादातर जिले राज्यों की सीमाओं और तीन राज्यों के मिलन बिंदु पर हैं। ऐसे में एक राज्य में नक्सल विरोधी अभियान चलने पर नक्सली दूसरे और दूसरे में चलने पर तीसरे राज्य में भाग जाते हैं। इन क्षेत्रों में नदियों का भी प्रवाह है और राज्यों की राजधानी से बहुत दूर हैं।